Publication Name: Dainik Jagran
Publication Date: 11/05/2026
Edition: Ranchi
Page No: 9
CCM: 286.64

Businesses from dairy to fisheries will be established in more than eight thousand PACS. An action plan for the development of PACS in the state will be implemented soon.

आठ हजार से ज्यादा पैक्सों में डेरी से लेकर मत्स्य पालन तक के होंगे व्यवसाय

राज्य में पैक्सों के विकास के लिए एक्शन प्लान बनाकर जल्द किया जाएगा लागू

दीनानाथ साहनी • जागरण

- अगले साल तक सभी पैक्सों का कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य
- हर पैक्स में डेरी और मत्स्य सहकारी समितियों का गठन
- पैक्स के स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

पटना : बिहार में 8463 पैक्सों में डेरी को बढ़ावा देने के साथ ही अब मत्स्य पालन को भी व्यवसाय के तौर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो और किसानों की आमदनी बढ़े, इसपर नई सरकार ज्यादा फोकस करने जा रही है। इसके लिए एक्शन प्लान बनाकर जल्द लागू किया जाएगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान-गेहूं समेत अन्य अनाज की खरीद, कृषि ऋण वितरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता में बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जाएगी।

एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य पैक्सों को केवल ऋण देने तक सीमित न रखकर उन्हें आत्मनिर्भर और बहुउद्देशीय बनाना भी है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने अफसरों के साथ अपनी पहली बैठक में पैक्सों के लिए आवश्यक निर्देश दिया है। इसमें स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने और बाजारों में किसानों के उत्पादों को सही कीमत दिलाने के उपायों पर भी भी काम करने के लिए कहा गया है। एक्शन प्लान को लागू करने से पहले पैक्सों से जुड़े किसानों से सुझाव मांगे जाएंगे। पैक्सों को उद्यमी के रूप में विकसित करने काम होगा, ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं आय अर्जित कर सकें।

एक करोड़ 25 लाख पैक्स सदस्य को किया जाएगा प्रशिक्षित : राज्य में 8463 पैक्स में एक करोड़ 25 लाख सदस्य हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 36 लाख है। साढ़े चार लाख नए सदस्य बनाए गए हैं। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पैक्स सदस्यों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। इसपर सरकार तेजी से काम करने जा रही है। अगले दो साल में प्रखंड स्तर पर पैक्स सदस्यों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार बन सकता है। सहकारी संस्थाएं केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांवों में सामाजिक सशक्तीकरण का भी बड़ा माध्यम हैं। इन संस्थाओं को मजबूत करने से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसान, महिलाएं तथा युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाना और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने मजबूत सहकारी नेटवर्क के जरिए छोटे किसानों और ग्रामीण उत्पादकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सहकारी संस्थाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सरकारी योजनाओं को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।